न्यूज पॉकेट

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सेनेटरी नेपकिन वेंडिग मशीन स्थापित

जोधपुर। महिला कल्याण संगठन उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर के सौजन्य से जोधपुर स्टेशन के प्लेटफार्म न.1 पर महिला शौचालय में एक सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन को स्थापित किया गया । इस अवसर पर सुनीता अरोरा, रिंकल भूतडा, विनीता मीणा, गीता मीणा एवं महिला कल्याण संगठन की अन्य महिलाएं मौजूद थी। उद्घाटन स्टेशन पर कार्यरत वरिष्ट महिला कर्मचारी श्रीमति सुमन देवी द्वारा किया गया। महिला यात्री इस वेंडिंग मशीन में 10 रूपये के सिक्कें डाल कर एक सेनेटरी नेपकिन पैड प्राप्त कर सकती है साथ ही प्रयोग में लिए गये नैपकिन को पास में लगे इन्सिनार्टर द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ये मशीन पर्यावरण अनुकूलित है। इसी के साथ ही जोधपुर स्टेशन पर रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओ के अन्तर्गत महिला यात्रियों के लिए एक और अच्छा कदम उठाया गया है।

वैल्यू सेगमेंट में कोमियो ब्रांड चरम पर

नई दिल्ली। साईबर मीडिया रिसर्च द्वारा बजट स्मार्टफोंस चैनल ऑडिट सर्वे 2018 के अनुसार हाल ही में लॉन्च किए गए मिड-सेगमेंट स्मार्टफोन ब्रांड, कोमियो को 'ओवरऑल ब्रांड सैटिस्फैक्शन' में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कोमियो इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुमित सहगल ने कहा एक मजबूत ऑफलाइन वितरण नेटवर्क का निर्माण हमारी विकास की योजनाओं के लिए बहुत जरूरी है। ब्रांड को न केवल ग्राहकों से, बल्कि हमारे वितरकों और रिटेलर्स से भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सीएमआर पर हेड-यूज़र रिसर्च प्रैक्टिस सत्य मोहंती ने कहा कोमियो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उत्पाद की संतुष्टि एवं सेल्स सपोर्ट में बहुत ऊंचा स्कोर हासिल किया।

राजस्थान के 5 छात्रों ने जीता प्रेमरिका स्प्रिट ऑफ कम्यूनिटी अवार्ड

जयपुर। डीएचएफएल प्रेमरिका लाइफ इंश्योरेंस (डीपीएलआई) द्वारा गुरुग्राम में आयोजित 8वें वार्षिक प्रेमरिका स्प्रिट ऑफ कम्यूनिटी अवार्ड ने सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में अपने असाधारण प्रयासों के लिए 29 स्कूल छात्रों को सम्मानित किया। ब्यावर, राजस्थान के सरकारी हायर सैकेंडरी स्कूल की सातवीं कक्षा के पांच छात्रों को अवार्ड दिया गया। डीपीएलआई के एमडी और सीईओ अनूप पाब्बी ने कहा सोका के माध्यम से, युवा स्वयंसेवकों की पहचान करते हैं जिन्होंने समाज में उनके काम के जरिए समाज में महत्वपूर्ण अंतर बनाया है। कार्यक्रम की एम्बेसेडर साइना नेहवाल ने कहा मुझे लगातार दूसरे वर्ष एसओसीए से जुड़े रहने का सम्मान मिला है। बच्चे हमारा भविष्य हैं और युवावस्था में समाज को वापस देने के अपने प्रयासों को प्रोत्साहित करना एक बहुत अच्छी पहल है।

बुक माइ शो से अब फ्री माइकूपन्स का लाभ

नई दिल्ली। ऑनलाइन टिकटिंग ब्रांड बुकमाइशो के उपभोक्ता अब बुकमाइशो प्लेटफॉर्म्स (वेबसाइट, एप्प, मोबाइल वेब) पर बुक कराई गई किसी भी टिकट के साथ माइकूपन्स का इस्तेमाल कर रेस्टोरेंट्स एवं कैफे के डिस्काउंट्स का लाभ उठा पायेंगे। बुकमाइशो के वाइस प्रेसिडेंट-बिजनेस इंटेलीजेंस एंड मार्केटिंग मार्जदी कल्यानीवाला ने कहा हम अपने यूजर्स के लिये माइकूपन्स के माध्यम से समग्र प्रस्ताव को सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें सभी शहरों में माइकूपन्स से बेहद शानदार प्रतिसाद मिला है और अब हम और भी उपभोक्ताओं को खुश करने के लिये इसका विस्तार करने के लिये काम कर रहे हैं।

डाय एंड मोल्ड इंटरनेशनल एग्जिबिशन मुंबई में

मुंबई। टूल एंड गॉज मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडिया (टैग्मा इंडिया) की ओर से 11 से 14 अप्रैल के बीच मुंबई के गोरेगांव में बॉम्बे एक्जिबिशन सेंटर में द्विवार्षिक डाय एंड मोल्ड इंटरनेशनल एक्जिबिशन का आयोजन किया जा रहा है। टैग्मा के प्रेसिडेंट डी.के. शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में भारत और विदेश की नामांकित कंपनियां प्रतिवर्ष अपनी नई तकनीक के साथ शामिल होती है उत्पादन स्तर बढ़ाने के साथ ही खर्च को करने वाले उत्पादन, तकनीक आदि पर ये कंपनियां विशेष जोर देती है।

विशाल डेटा के लिए अडवांस प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली। सरकार देश के विशाल डेटा को संभालने और समझने के लिए एक अडवांस टेक्नॉलजी प्लैटफॉर्म बनाने पर विचार कर रही है। इससे नागरिक सरकारी खर्च और नीतियों की सफलता, उपभोग ट्रेंड आदि को समझने में मदद मिलेगी। हालांकि डेटा समग्र रूप में होगा और व्यक्तिगत व पहचान योग्य डेटा संग्रह नहीं किया जाएगा।

इसके पीछे उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना है और नागरिकों को भी इस डेटा तक पहुंच दी जाएगी। इस टेक्नॉलजी की मदद से डेटा केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से हासिल किया जाएगा ताकि बेहतर नीति निर्माण में मदद मिल सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि नीति आयोग निजी संस्था के मिलकर नैशनल डेटा ऐंड एनालिटिक्स प्लैटफॉर्म विकसित करने के विचार पर काम कर रहा है। नीति आयोग इस प्लेटफॉर्म के विकास और संचालन के लिए पार्टनर की तलाश में जुटा है। बताया जा रहा है कि डेटा के गहरे विश्लेषण के लिए आर्टफिशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। नागरिकोंए नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए यह क्षेत्रवार डेटा का एकमात्र स्रोत होगा। आईटी मंत्रालय के पास ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लैटफॉर्म है जिस पर डेटा के सैकड़ों समूह हैं लेकिन इस पर विश्लेषण की क्षमता नहीं है।

सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन

जयपुर। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग एवं मारूति सुजूकी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वधान में चल रही सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का समापन शुक्रवार को हुआ। जनपथ श्याम नगर स्थित के.पी. ओटोमोटिव मारूति ड्राईविंग स्कूल में हुई कार्यशाला में सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई एवं सभी उपस्थित चालकों की निशुल्क नेत्र जांच सेन्टर फॉर साइट आई हॉस्पीटल वैशाली नगर जयपुर के माध्यम से कराई गयी। इसमें कुल 11 बैच में लगभग 200 वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। समापन के अवसर पर राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग के नियन्त्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव जयपुर महेन्द्र सोनी एवं परिवहन विभाग की उप परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) निधि सिंह शामिल हुए। कार्यशाला के मुख्य संचालक परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, सह संचालक विरिष्ठ वाहन प्रक्षिक्षक पंकज सिंह तड़ागी व वाहन प्रक्षिशक उत्तम सिंह राठौड़ (के. पी. ऑटोमोटिव्स) के द्वारा प्रत्येक बैच को सड़क सुरक्षा जागरुकता से अवगत कराया गया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल कुमार जैन, परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, मारुति सुजुकी इंडिया ली. के राजस्थान हैड सतीश सिंह, केपी ऑटोमोटिव्स के एक्जीक्युटिव डायरेक्टर शंशाक पोद्दार व एम.डी.एस. मैनेजर प्रिती राठौर व सेन्टर फॉर साइट नेत्र चिकित्सालय से विशाल मौजूद थे।

अफसरों ने मुआवजे के हड़पे 9.52 करोड़

हरियाणा के कुछ अफसरों ने भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि अपने बैंक खाते में जमा कराई और इससे मिली 9.52 करोड़ के ब्याज की राशि हड़प ली

अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि को सरकारी खाते की बजाय खुद के खातों में जमा करा लिया 9.52 करोड़ के ब्याज का लाभ

चंडीगढ़

हरियाणा के अधिकारियों ने विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि की मुआवजे की राशि बैंकों में सरकारी खाते में जमा कराने के बजाय अपने खुद के नाम से खाते खुलवा कर उनमें जमा करा दी। इन खातों पर मिली ब्याज की 9.52 करोड़ रुपये की राशि भी सरकारी कोष में जमा नहीं कराई और हड़प गए। प्रदेश सरकार को अधिकारियों के इस कारनामे से 15 करोड़ 81 लाख रुपये का नुकसान अलग से उठाना पड़ा। इस तरह सरकार को लगभग 25 करोड़ का नुकसान हुआ।

अफसरों ने सारा खेल गिफ्ट, कमीशन और ब्याज के चक्कर में किया और सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान कर दिया। विभिन्न जिलों में राजस्व अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख सरकारी पैसा अपने निजी खातों में रखा और सरकार को करीब 25 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान पहुंचाया। इसमें से ब्याज के साढ़े नौ करोड़ रुपये इन अफसरों ने खुद खा लिए। सरकार के संज्ञान में जब यह प्रकरण आया तो आनन-फानन में सभी अफसरों को सूद समेत सारा पैसा सरकारी खातों में जमा कराने के निर्देश जारी हुए। इसके बावजूद किसी अफसर ने यह राशि जमा नहीं कराई है। अफसरों की बैंक अधिकारियों से सांठगांठ से यह खेल चलता रहा। सरकारी राशि पर ब्याज और मोटे उपहारों के चलते इन अफसरों ने विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि की राशि सरकारी खातों में जमा नहीं होने दी। सारी राशि निजी बैंक खातों में जमा कराई गई। इस बात का उल्लेख कैग ने अपनी रिपोर्ट में किया है।

सरकार को 15.81 करोड़ रुपए का नुकसान

अधिकारियों ने बैंकों में न केवल अपने नाम से करंट और सेविंग अकाउंट खुलवा लिए बल्कि इन खातों पर मिले ब्याज के 9 करोड़ 52 लाख रुपये भी सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए। इसके अलावा सरकार को 15.81 करोड़ रुपये का भारी नुकसान अलग से उठाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अफसरों ने राजस्व जमा खाते आरडी खोलने की बजाय बिना ब्याज वाले करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खुलवा दिए। इन खातों में जो राशि जमा हुई वह सरकारी थी जो कि सरकार ने ब्याज पर ले रखी थी। सरकार को बैंक खातों से ब्याज तो मिला नहीं लेकिन जहां से यह राशि ली गई थी उसका ब्याज जरूर भरना पड़ा।

विभागाध्यक्ष नहीं खोल सकता बैंक खाता

वित्त विभाग की ओर से 2 दिसंबर 2011 को जारी आदेश के मुताबिक कोई भी विभागाध्यक्ष अपने नाम से बैंक खातों का संचालन नहीं कर सकता। ऐसे में सभी निजी खातों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए। जून 2014 में वित्त विभाग के नए आदेश जारी हुए। इनमें कहा गया कि ऐसे तमाम सरकारी विभाग जो अपनी विकास परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं वे सरकारी खजाने में अपेक्षित बिल प्रस्तुत कर बुक हस्तांतरण के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिकारियों एलएसी के राजस्व खाते आरडी में अपेक्षित राशि जमा करा दें। बताया जाता है कि जब कभी भूमि अधिग्रहण अधिकारी को किसी लाभार्थी को भुगतान करना हुआ तो वह खजाने में आरडी खाते से आहरण बिल प्रस्तुत करेगा और अधिग्रहीत जमीन की राशि का भुगतान संबंधित जमीन मालिक के खाते में इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली ईपीएस के माध्यम से चला जाएगा। इसके बावजूद अफसरों ने नियमों का पालन नहीं किया।

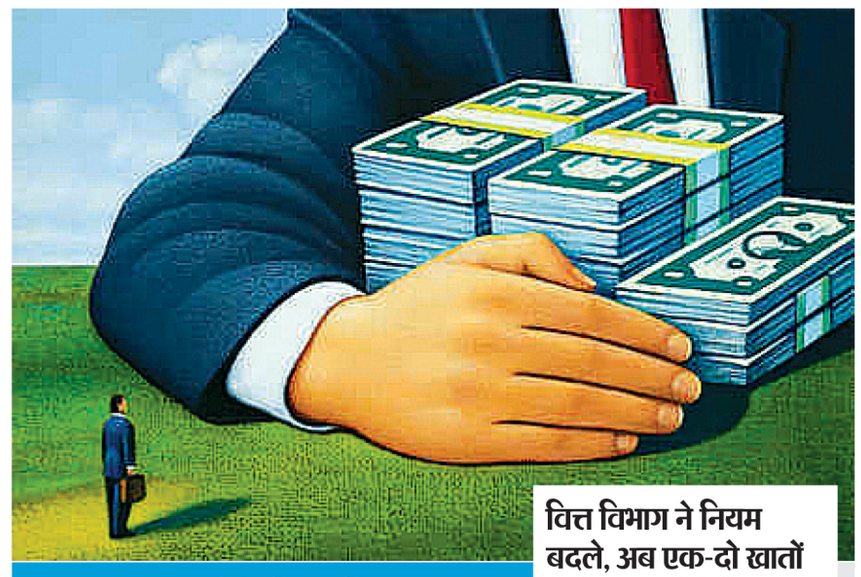

अब हर महीने वित्त विभाग को देना पड़ेगा लेन-देन का ब्योरा

ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं। सरकार इस पर गंभीर है। सरकारी विभागों द्वारा बैंकों से लेन.देन के लिए नए मानक निर्धारित किए हैं। नई पॉलिसी से वित्तीय संस्थाओं से लेन.देन में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी। हर महीने सरकारी विभागों द्वारा बैंकों में जमा कुल राशि और लोन की जानकारी संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण विभाग आइएफसीसी में देना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई महकमा तीन महीने तक के लिए बैंकों में दस करोड़ रुपये से अधिक जमा करना चाहता है तो उसे दस दिन पहले ही आइएफसीसी को प्रस्ताव भेजना होगा ताकि समेकित प्रस्ताव तैयार किया जा सके। आइएफसीसी के अनुमोदन के बिना कोई भी संगठन किसी योजना के लिए बैंक खाता नहीं खोल सकेगा। इसके अलावा कोई भी महकमा वास्तविक खर्च किए बिना बैंक खाते में रखने के लिए पैसे नहीं निकाल सकता। यदि किसी महकमे की धनराशि बैंकों में बेकार पड़ी रहती है तो उससे दो फीसदी ब्याज वसूल किया जाएगा।

वित्त विभाग ने नियम बदले, अब एक-दो खातों में ही रख सकेंगे पैसा

सरकारी महकमों के दर्जनों बैंक खातों पर सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। अब सभी महकमे एक या दो बैंकों में ही खाते खोल सकेंगे। अधिकतम ब्याज देने वाले बैंकों में सरकारी पैसा जमा किया जाएगा और न्यूनतम ब्याज लेने वाले बैंकों से ही लोन लेने की मंजूरी होगी। इसके अलावा वित्त विभाग से रकम लेने के बावजूद खर्च नहीं करने वाले महकमों से दो फीसद जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। तीन महीने तक दस करोड़ रुपये जमा करने या ऋण लेने के लिए विभाग पैनल के बैंकों से कोटेशन मांगेंगे। कोटेशन मिलने के दो दिन में जमा राशि रखने के लिए अधिकतम ब्याज दर देने वाले तथा लोन के लिए न्यूनतम ब्याज दर वाले बैंक का चयन किया जाएगा।

पंचकूला, फतेहबाद व रोहतक में भी नुकसान

पंचकूला, फतेहाबाद व रोहतक के जिला राजस्व एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के पास जमीनों के अधिग्रहण के लिए बैंक ड्राफ्ट तथा चेक के माध्यम से 2012 से 2017 के बीच 737 करोड़ 71 लाख रुपये जमा हुई। पंचकूला में 212.21 करोड़, फतेहबाद में 460 करोड़ तथा रोहतक में 65 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि आई। इन तीनों जिलों के अधिकारियों ने राजस्व जमा खाते आरडी खोलने की बजाय बिना ब्याज वाले 11 चालू खाते करंट अकाउंट खुलवा दिए। इसके अलावा 58 बचत बैंक खाते सेविंग अकाउंट खोले गए तथा सारी राशि इन सभी खातों में जमा करा दी। मार्च 2017 तक इन सेविंग अकाउंट्स में 54.37 करोड़ रुपये की राशि रखने के कारण 15.81 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा क्योंकि इस राशि को विभिन्न विभागों ने ब्याज पर ही उठा रखा था।

डीआरओ ने साधी चुप्पी, दो ने दी सफाई

हरियाणा की प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा महुआ पाल ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों की चालाकी को उजागर किया है। 52 बचत खातों में 9 करोड़ 52 लाख रुपये का ब्याज मिला किंतु इस राशि को जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों ने अक्टूबर 2017 तक भी सरकारी खातों में जमा नहीं कराया। फतेहबाद के डीआरओ ने कैग को अपने जवाब में कहा है कि वहां के डीसी के निर्देश पर करंट अकाउंट्स में राशि जमा कराई गई थी। पंचकूला के जिला राजस्व अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि प्राइवेट बैंक के खातों को छोड़कर सभी स्कीमों के बैंक खाते बंद कर दिए। दलील दी कि विजिलेंस की एक जांच के कारण प्राइवेट बैंक का खाता बंद नहीं कराया जा सकता। रोहतक के जिला राजस्व अधिकारी की ओर से अक्टूबर 2017 तक कोई जवाब कैग के पास दाखिल नहीं किया गया था।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग का उद्घाटन, गंदगी के ढेर में दब रहा रामलीला मैदान

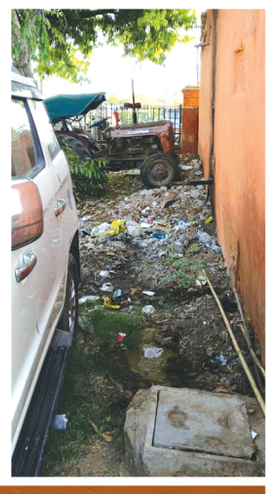

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ने ई-रिक्शाओं के चार्ज के लिए दी सुविधा, लेकिन नहीं हो रहा उपयोग

जयपुर। सांगानेरी गेट स्थित रामलीला मैदान में कुछ दिनों पहले ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया जहां पर ई-रिक्शा को चार्ज किया जा सकता है परंतु महज 15 दिनों में ही मैदान के चारों ओर गंदगी का ढेर लग चुका है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर द्वारा स्थापित 12 केवीपी सौर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन 18 मार्च को भारी उद्योग विभाग के निदेशक प्रवीण एल अग्रवाल द्वारा किया गया था।

उद्घाटन के मौके पर जयपुर नगर निगम के मुख्य अधिशाशी अधिकारी रवि जैन भी मौजूद थे परंतु नगर निगम के दूसरे अभियान स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस उद्देश्य से ये चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया था वो तो दूर की बात है, चार्जिंग स्टेशन की देखरेख के लिए भी एक आदमी नहीं मौजूद है। आवारा पशुओं का दिन-भर वहां आना जाना रहता है। चार्जिंग स्टेशन बना तो दिया गया है परंतु उसे शुरू नहीं किया गया है।

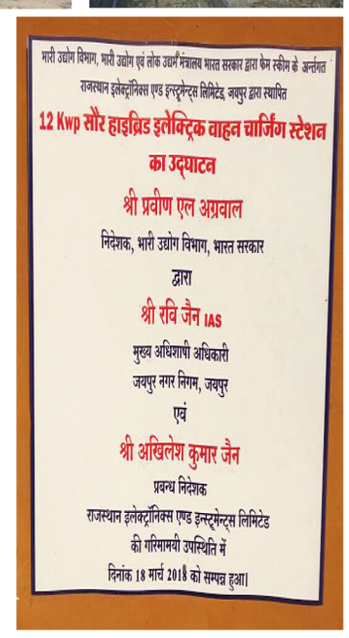

ड्राई डे पर क्लबों में बेची शराब, प्रशासन और पुलिस खामोश

आबकारी विभाग के आदेश के बाद भी क्लबों ने की मनमानी, खोले क्लब और परोसी शराब

जयपुर। शहर के अशोक नगर क्षेत्र में महावीर जयंती के मौके पर क्लब में शराब बेची गई। महावीर जयंती जो कि प्रदेश सरकार ने ड्राय डे घोषित किया हुआ था और उस दिन शहर के ज्यादात्तर क्लबों ने ड्राय डे होने की वजह से क्लब को बंद रखा था परंतु अहिंसा सर्किल स्थित ब्लैक आउट क्लब में खुलकर शराब बेची गई.

इतना ही नहीं जयपुर के अशोक नगर थाना क्षेत्र में आने वाले क्लब ब्लैक आउट जो कि अहिंसा सर्किल स्थित होटल गोल्डन ओक में है. यह कि महावीर जयंती के मौके पर वहां पर खुलेआम शराब की बिक्री हुई और सभी को शराब परौसी गई. जैन समाज का पवित्र दिन होने की वजह से आबकारी विभाग के आदेश के तहत ड्राई डे घोषित था और राजस्थान आबकारी नियम के अनुसार उस दिन शराब परौसना और शराब बेचना अपराध होता है.

नियमों की अवहेलना

अहिंसा सर्किल स्थित ब्लैक आउट में सुखा दिन के मौके पर न केवल क्लब खोला बल्कि खुलेआम शराब परौसी गई. क्लब में राजस्थान आबकारी नियमों का भी ध्यान नहीं रखा गया. उसके बाद थानाअधिकारी अशोक नगर में इसके खिलाफ शिकातय देकर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई परंतु प्रशासन की ओर से कार्रवाई तो दूर इस मामले की जांच तक नहीं की गई।

पारा 33.5 डिग्री, फिर भी चार माह की बच्ची आई स्वाइन फ्लू की चपेट में

राजीव मेहता, जोधपुर

शहर में गर्मी की असर होने के बावजूद स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। शहर में तापमान 33.5 होने के बाद भी चार माह की बच्ची स्वाइन फ्लू की चपेट में आई। विशेषज्ञों की मानें तो स्वाइन फ्लू का वायरस नमी में सक्रिय होता है। ज्यादा गर्मी होने पर उसका असर कम हो जाता है। कुछ दिन शांति के बाद एक और पॉजिटिव मरीज सामने के चलते पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 109 और मरने वाले मरीज 26 हो गए हैं। पॉजिटिव मरीज बालेसर निवासी है। डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कुल 13 सैंपल लगाए गए जिनमें से 1 पॉजिटिव आया है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब शहर में स्वाइन कि अब शहर में स्वाइन फ्लू लगभग समाप्त हो चुका है जो सामने आने वाले मरीज कहीं बाहर से ट्रेवल करके यहां आ रहे हैं।